

विविध नागरिक

माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला और आर.एन.मिस्तल के समक्ष

मुंशी याचिकाकर्ता - अपीलकर्ता

बनाम

पुत्रा राम-प्रतिवादी.

सी. विविध. संख्या 1919-सी., 1973

ई.एफ.ए. संख्या 310, 1973

29 अक्टूबर 1973.

परिसीमा अधिनियम (1963 का XXXVI)-1963) धारा 5 और 14-धारा 14 में विचारित परिस्थितियाँ-क्या धारा 5 के तहत "पर्याप्त कारण" माना जा सकता है-किसी मुकदमे या आवेदन और उसके सिद्धांतों पर धारा 14 की प्रयोज्यता अपील के लिए बताए गए "पर्याप्त कारण" के बीच अंतर - प्रत्येक दिन की देरी के लिए पर्याप्त कारण के सबूत का अर्थ - क्या धारा 5 के तहत विवेक के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है।

यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 केवल मुकदमों और आवेदनों पर लागू होती है, अपीलों पर नहीं, फिर भी धारा में विचार की गई परिस्थितियों को उचित रूप से दिए गए अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" के रूप में लिया जा सकता है। अपील के प्रयोजनों के लिए भी अधिनियम की धारा 5 में वाक्यांश। एक ओर किसी मुकदमे या आवेदन पर धारा 14 की प्रयोज्यता और दूसरी ओर किसी अपील पर इसके सिद्धांतों को लागू करने के बीच एकमात्र अंतर यह है कि यह वादी या आवेदक को वह अवधि प्राप्त करने का अधिकार देता है जिसके दौरान मुकदमा या आवेदन लंबित था और गलत न्यायालय में सद्भावपूर्वक मुकदमा चलाया गया था, इसे अधिकार के मामले के रूप में बाहर रखा गया है, अपील के मामले में अधिनियम की धारा 5 के तहत उस प्रावधान के सिद्धांतों के आधार पर उपाय विवेकाधीन है। यदि धारा 14 की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उन्हें उस अर्थ में पर्याप्त कारण माना जाता है, तो न्यायालय सही न्यायालय में अपील दायर करने में देरी को माफ कर सकता है। अधिनियम की धारा 5 में अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। भले ही सद्भावना और उचित परिश्रम के विचार, जो धारा 14 के आवश्यक तत्व हैं, अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही की कठोरता में लागू नहीं हो सकते हैं, सद्भावना की कमी या कमी कभी भी पर्याप्त कारण के अनुमान को उठाने को उचित नहीं ठहरा सकती है, किसी भी परिस्थिति में।

निर्णय लिया गया कि अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" जैसा कि धारा 5 में प्रयोग किया गया है अधिनियम का मतलब एक ऐसा कारण है जो पार्टी के नियंत्रण से परे है किसी पक्ष द्वारा देरी के लिए अनुभाग की सहायता या कारण का आह्वान करना उचित देखभाल और ध्यान के बावजूद संभवतः इसे टाला नहीं जा सकता था, सीमा

अवधि के बाद अपील पर मुकदमा चलाने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 के तहत विवेक के प्रयोग के लिए एक शर्त है।

परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 5 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि विलंब माफ किया जाए और अपील स्वीकार की जाए।

(मूल केस संख्या 230/1972, श्री पी. एल. सांघी वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, करनाल द्वारा 18 जनवरी 1973 को निर्णय दिया गया)।

याचिकाकर्ता के वकील डायली राम पुरी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता जी.सी.मित्तल।

आर. एस. नरूला, जे.-

वन दरिया राम (जिन्हें इस अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है) ने वादी-प्रतिवादी (बाद में इसे कहा जाएगा) पुत्रा राम को विवाद में संपत्ति की बिक्री के लिए एक लिखित समझौता किया था। डिक्री-धारक) 30 अगस्त, 1967 को, जिसमें वह 5 जून, 1968 को या उससे पहले बिक्री-विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ था। डिक्री-धारक को पता चला कि दरिया राम बेचकर समझौते का उल्लंघन करने का प्रस्ताव कर रहा था। मुंशी अपीलकर्ता (बाद में निर्णय-देनदार के रूप में संदर्भित) के लिए प्रश्न में संपत्ति, और इसलिए, दरिया राम के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया ताकि उसे निर्णय-देनदार को संपत्ति बेचने से रोका जा सके। निर्णय-देनदार, जिसे उस मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में भी शामिल किया गया था, ने इसका विरोध किया, अपना लिखित बयान दाखिल किया और यहां तक कि उस मुकदमे में गवाह के रूप में भी पेश हुआ। यह कहा गया है कि निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ एक आपत्ति पर, उक्त मुकदमे को डिक्री-धारक द्वारा वापस ले लिया गया था और उसके बाद बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा, जिससे वर्तमान कार्यवाही उत्पन्न हुई है, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। निषेधाज्ञा के मुकदमे को खारिज करने और विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे की स्थापना के बीच की अवधि में, दरिया राम ने संपत्ति निर्णय-देनदार को दे दी। निर्णय-ऋणी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए भी मुकदमे का विरोध किया, लेकिन अंततः 23 जुलाई, 1971 को ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर फैसला सुनाया गया। 1971 की नियमित प्रथम अपील संख्या 350 के साथ, जो निर्णय-ऋणी द्वारा डिक्री के खिलाफ दायर की गई थी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा कब्जे के लिए- बिक्री के लिए समझौते का गठन, निर्णय-देनदार ने किया उस डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए आवेदन। 11 अगस्त, 1971 को अपील स्वीकार करते हुए, दिल्ली, जे. ने दूसरे पक्ष को रोक के आवेदन की सूचना के साथ निष्पादन कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। निर्णय-देनदार और डिक्री-धारक, दिल्ली के वकील को सुनने के बाद, जे ने अपने विस्तृत आदेश, दिनांक 6 सितंबर, 1971 द्वारा नियमित प्रथम अपील में उक्त आवेदन (सी.एम. 2391-सी, 1971) को खारिज कर दिया और रद्द कर दिया। 11 अगस्त, 1971 को विद्वान न्यायाधीश द्वारा एकपक्षीय स्थगन दिया गया

था। नियमित प्रथम अपील को इस न्यायालय में सही ढंग से दायर किया गया था क्योंकि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का न्यायिक मूल्य रु। था। 25,000.

(2) उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के हटने के बाद, निर्णय-ऋणी ने निष्पादन न्यायालय में डिक्री के निष्पादन के खिलाफ आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें 13 जनवरी, 1973 को खारिज कर दिया गया। हालांकि निर्णय-ऋणी ने स्वयं नियमित दायर किया था इस न्यायालय में डिक्री के खिलाफ पहली अपील, उन्होंने 18 जनवरी, 1973 के निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी अपील को प्राथमिकता देने के लिए एक गलत मंच चुना। उन्होंने 15 फरवरी, 1973 को विद्वान जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष अपील दायर की। अपील के ज्ञापन के साथ, निर्णय-ऋणी ने अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। उसी दिन, यानी 15 फरवरी, 1973 को अपील स्वीकार करते हुए, विद्वान जिला न्यायाधीश, करनाल ने 19 सितंबर, 1973 के लिए डिक्री धारक को अपील का नोटिस और आवेदन की सूचना जारी की थी। 4 अप्रैल, 1973. उन्होंने निष्पादन कार्यवाही पर एकपक्षीय और अंतरिम रोक भी लगा दी। चूंकि स्थगन आवेदन के निस्तारण के लिए लंबी तारीख दी गई थी, इसलिए डिक्री धारक ने 28 फरवरी 1973 को नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 4 के तहत एक पक्षीय स्थगन आदेश को हटाने के लिए आवेदन किया। दो आधार, अर्थात्, (i) जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास अपील पर विचार करने या उससे निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि जिस मुकदमे से निष्पादन की कार्यवाही उत्पन्न हुई थी उसका मूल्यांकन रु। 25,000; और (ii) उच्च न्यायालय ने पहले ही 6 सितंबर 1971 को स्थगन आदेश हटा दिया था। जब आवेदन विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने डिक्री-धारक को पहले से ही तारीख के लिए नोटिस जारी करने का विकल्प चुना। स्थगन कार्यवाही में, जो 4 अप्रैल, 1973 के लिए निर्धारित है। निर्णय-देनदार के विद्वान वकील श्री डायली राम पुरी ने इस पर कोई विवाद नहीं किया है कि स्थगन हटाने के लिए आवेदन की एक प्रति के साथ उस आवेदन की सूचना दी गई थी। 4 अप्रैल, 1973 से पहले निर्णय-ऋणी-अपीलकर्ता पर कार्य किया गया, और निर्णय-ऋणी-अपीलकर्ता उस पर विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ। उस नोटिस के अनुसरण में दिन. स्थगन कार्यवाही की सुनवाई की तारीख पर, निर्णय-देनदार ने एक पक्षीय रोक को हटाने के लिए आवेदन पर एक लिखित उत्तर दायर किया जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला न्यायाधीश के पास न कि उच्च न्यायालय के पास निष्पादन अपील सुनने का आर्थिक क्षेत्राधिकार था। . यह कुछ हद तक अजीब है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने उस दिन स्थगन मामले का फैसला नहीं किया, बल्कि केवल यह निर्देश दिया कि स्थगन के आवेदन के साथ-साथ एकपक्षीय स्थगन को हटाने के आवेदन पर सितंबर में अपील के साथ ही सुनवाई की जाएगी। 19, 1973, जिस तारीख के लिए अपील में नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था। हमारी राय में, 4 अप्रैल, 1973 का स्थगन आदेश वस्तुतः अपील की सुनवाई तक स्थगन आदेश की पुष्टि करने के बराबर था, और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक पक्षीय रोक को हटाने के लिए आवेदन को खारिज करने के समान था। आदेश देना।

(3) ऊपर उल्लिखित स्थिति का सामना करते हुए, डिक्री धारक इस न्यायालय में पहुंचा और 15 फरवरी 1973 के विद्वान जिला न्यायाधीश के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ और 1973 का सिविल रिवीजन 535 दायर किया। उस

न्यायालय का आदेश, दिनांक 4 अप्रैल, 1973, जिसके द्वारा उन्होंने एकपक्षीय रोक हटाने के लिए आवेदन का निपटारा नहीं किया था। इस न्यायालय (दिल्ली, जे.) द्वारा निर्णय-देनदार को नोटिस देने और 31 मई, 1973 को उसके वकील को सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई थी। जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए यह विशेष रूप से देखा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा 6 सितंबर, 1971 के आदेश द्वारा निष्पादन की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद जिला न्यायाधीश को रोक नहीं लगानी चाहिए थी। जब निर्णय-ऋणी ने पाया कि स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया था, और ट्रायल कोर्ट के डिक्री के निष्पादन में उसे बेदखल करना होगा, वह जिला न्यायाधीश की अदालत में गया और उस अदालत में इस आधार पर अपील वापस करने के लिए एक आवेदन किया कि जिला न्यायाधीश की अदालत के पास अपील सुनने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार का अभाव था। उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वास्तव में उन्होंने 4 अप्रैल, 1973 को जिला न्यायाधीश के समक्ष डिक्री-धारक के आवेदन के जवाब में न केवल लिखित रूप में इसका विरोध किया था, बल्कि उस बिंदु पर डिक्री-धारक के साथ विवाद भी किया था। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान यह उस स्थिति में था कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्पादन अपील की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के प्रश्न को खुला छोड़ दिया था क्योंकि वह बिंदु अपील में ही विचाराधीन था जो उस समय जिला के समक्ष विचाराधीन था। न्यायाधीश। फिर भी, अचानक उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाए जाने के बाद उन्हें सही कानूनी स्थिति का पता चला। विद्वान जिला न्यायाधीश ने कथित तौर पर निर्णय-देनदार के आवेदन पर दिनांक 6 जून, 1973 को एक पक्षीय आदेश पारित किया, उस आवेदन की सूचना डिक्री-धारक को दिए बिना, जो अपील में एक पक्ष था, और जिस पर अपील का नोटिस 19 सितंबर, 1973 को पहले ही दिया जा चुका था। विद्वान जिला न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता (निर्णय-देनदार) के वकील के बयान के अनुसार, मामले में क्षेत्राधिकार मूल्य रु. 26,000, और अपील, इसलिए, उच्च न्यायालय में दायर करने के बजाय गलत तरीके से उनके न्यायालय में दायर की गई थी। इसलिए, उन्होंने (6 जून, 1973 को) आदेश दिया कि अपील का न्यायिक मूल्य रु. 26,000, अपील गलत तरीके से उनके न्यायालय में दायर की गई थी और इसे उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए (निर्णय-देनदार-अपीलकर्ता को) वापस किया जाना चाहिए। निर्णय-ऋणी ने उसी दिन जिला न्यायाधीश की अदालत से अपील वापस लेने में कोई समय नहीं गंवाया और 7 जून, 1973 को विविध आवेदनों के साथ इसे इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। सी.एम. में 1918-सी 1973, संहिता के आदेश 41 नियम 5 के तहत, अपील के अंतिम निर्णय तक विचाराधीन डिक्री के निष्पादन में निर्णय-ऋणी की बेदखली पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना की गई थी। सी.एम. में 1919-सी 1973 में, प्रार्थना इस आधार पर परिसीमा अधिनियम (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 5 के तहत अपील दायर करने में देरी या समय के विस्तार को माफ करने के लिए थी कि अपील की प्रस्तुति में देरी एक हड़्डी के कारण हुई थी जिला न्यायाधीश, करनाल की अदालत में अपील दायर करने में गलती हुई।

(4) चूँकि निष्पादन प्रथम अपील और दो आवेदन अवकाश के दौरान दायर किए गए थे, उन्हें कोशल, वी.जे. के समक्ष रखा गया, जिन्होंने 11 जून, 1973 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: - "मोशन बेंच द्वारा सुनवाई तक बेदखली पर रोक लगाई जाए। सी.एम. 1919-सी/73 को भी आदेश के लिए उस बेंच के समक्ष रखा जाएगा।" विद्वान अवकाश न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में अपील एवं सी.एम. 1973 के 1919-सी, प्रस्ताव सुनवाई के लिए 24 अगस्त 1973 को हमारे सामने रखे गए थे। हमने सी.एम. को नोटिस दिया. केवल उस अवस्था में. उस नोटिस के जवाब में, डिक्री-धारक श्री गोकल चंद मित्तल, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ है, और समय विस्तार के लिए आवेदन का जोरदार और गंभीरता से विरोध किया है।

(5) हालाँकि अधिनियम की धारा 14 केवल मुकदमों और आवेदनों पर लागू होती है, अपीलों पर नहीं, जिन परिस्थितियों पर विचार किया गया है धारा में उचित रूप से गठन के लिए लिया जा सकता है: अपील के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 5 में उस वाक्यांश को दिए गए अर्थ के भीतर एक "पर्याप्त कारण"। ए, शुरुआती दिनों में कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया विपरीत दृष्टिकोण इस विषय पर कानूनी प्राधिकरण की सहमति के खिलाफ है। एक ओर किसी मुकदमे या आवेदन के मामले में धारा 14 की प्रयोज्यता और दूसरी ओर अपील के मामले में धारा 14 के सिद्धांतों के आह्वान के बीच एकमात्र अंतर यह है जबकि धारा 14 वादी या आवेदक को उस अवधि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है जिसके दौरान मुकदमा या आवेदन लंबित था और गलत न्यायालय में 'सच्चाई के आधार पर मुकदमा चलाया गया था' को अधिकार के मामले के रूप में बाहर रखा गया था, उस के सिद्धांतों के आधार पर उपचार अपील के मामले में अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रावधान विवेकाधीन है, और यदि धारा 14 की आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, और तथ्यों पर और अदालत सही अदालत में अपील दायर करने में देरी को माफ कर सकती है। दिए गए मामले की परिस्थितियों में उन्हें उस अर्थ में पर्याप्त कारण माना जाता है जिसमें उस अभिव्यक्ति का उपयोग अधिनियम की धारा 5 में किया जाता है। भले ही सद्भावना और उचित परिश्रम के विचार, जो धारा 14 के आवश्यक तत्व हैं, अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्यवाही की कठोरता में लागू नहीं हो सकते हैं, सद्भावना की कमी या कमी कभी भी एक निष्कर्ष निकालने को उचित नहीं ठहरा सकती है। किसी भी परिस्थिति में पर्याप्त कारण।

(6) देरी की माफी के लिए आवेदन के पैराग्राफ 7 में दिए गए पर्याप्त कारण को निम्नलिखित भाषा में लिखा गया है: - "कुछ दिन पहले यह पता चला कि अपील का निष्पादन जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि यह केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य था; जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की गलत प्रस्तुति हुई थी। तथ्य यह है कि मुकदमे के दावे का क्षेत्राधिकार मूल्य उस आदेश में इंगित नहीं किया गया था जिसके खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई थी।" आवेदन के उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होते हैं। आवेदन दिनांक 6 जून 1973 का है। निष्पादन अपील की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में आर्थिक क्षेत्राधिकार का दोष स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले लिखित रूप में निर्णय-देनदार के ध्यान में लाया गया था। 4 अप्रैल 1973 से पहले, डिक्री-धारक के जिले में आवेदन में न्यायाधीश एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त करें। नोटिस के बावजूद उस दोष के बारे में उन्होंने 4 अप्रैल, 1973 को जिला

न्यायाधीश की अदालत में न केवल अपील के मंच के बारे में अपने फैसले पर जोर दिया था, बल्कि 1973 के सिविल रिवीजन 535 की सुनवाई में भी उस स्थिति पर कायम रहे थे। 31 मई, 1973 को दिल्ली, जे. के समक्ष। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जबकि पहले के चरणों में निर्णय-देनदार का जानबूझकर प्रयास अधिकार क्षेत्र के दोष की सूचना के बावजूद जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील को लंबित रखना था। दलील यह है कि यह जिला न्यायाधीश की अदालत थी जिसके पास वास्तव में अपील पर विचार करने और सुनने का अधिकार क्षेत्र था, उन्होंने अब इस आवेदन में एक बिल्कुल असंगत दलील दी है कि निष्पादन अपील जिला न्यायाधीश की अदालत में एक द्वारा दायर की गई थी। निष्पादन के विरुद्ध आपत्तियों को खारिज करने वाले निष्पादन न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी मूल्य का संकेत नहीं दिए जाने के कारण हुई त्रुटि। यदि निर्णय-देनदार हमें अपने आवेदन के अनुच्छेद 7 में बताए गए आधार की सच्चाई के बारे में आश्वस्त करने में सक्षम था, तो यह वास्तव में विचार के योग्य होता; लेकिन यह दलील प्रथम दृष्टया उन परिस्थितियों में अक्षम्य है जिसका विस्तृत संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा, इस मामले की परिस्थितियों में संभवतः यह नहीं माना जा सकता है कि निर्णय-देनदार जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा था, खासकर 4 अप्रैल, 1973 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान। 6 जून 1973। उचित परिश्रम साबित करने का भार धारा 14 के प्रावधान या सिद्धांतों के लाभ का दावा करने वाले वादी पर है। इस मामले के तथ्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि निर्णय-देनदार ने अदालत में अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी कुछ संभावित गलती के कारण जिला न्यायाधीश की याचिका, और 4 अप्रैल, 1973 के बाद, 6 जून, 1973 तक उस न्यायालय में अपील जारी रखना, किसी भी मामले में, प्रामाणिक नहीं था। परिसीमा अवधि के बाद अपील पर मुकदमा चलाने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण अधिनियम की धारा 5 के तहत विवेक के प्रयोग के लिए एक शर्त है। न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त कारण की लगातार व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ है एक ऐसा कारण जो अनुभाग की सहायता लेने में पार्टी के नियंत्रण से परे है या देरी का कारण है जिसे एक पार्टी संभवतः उचित देखभाल और ध्यान के बावजूद टाल नहीं सकती थी। इस मामले में निर्णय-देनदार को उन दोनों परीक्षणों में असफल होना होगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिस्थितियों में निर्णय-देनदार द्वारा स्थगन के लिए आवेदन के साथ-साथ समय बढ़ाने के लिए भी आवेदन दायर किया गया है- यह रुख न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(7) श्री गोकल चंद मित्तल का कहना है कि डिक्री धारक थे विद्वान अवकाश न्यायाधीश द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की जानकारी नहीं है जब डिक्री धारक ने 15 जून, 1973 को डिक्री के निष्पादन में विवादित संपत्ति पर वास्तव में कब्जा कर लिया। दूसरी ओर, श्री पुरी का कहना है कि डिक्री धारक को स्थगन आदेश के बारे में पता था और अवमानना कार्यवाही के लिए एक आवेदन दिया गया था। उसके मुकदमे द्वारा डिक्री-धारक के खिलाफ पहले ही दायर किया जा चुका है। हम उस मामले पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचते हैं।

(8) उपर्युक्त परिस्थितियों में हमें सी.एम. को अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं दिखता। 1973 का 1919-सी, समय के विस्तार के लिए, और लागत के साथ इसे खारिज करने में कोई संकोच नहीं है। वकील की फीस रु. 200.

(9) चूँकि अपील समय से बाधित है, इसलिए इसे तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। चूँकि अब तक अपील की कोई सूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। सेमी। 1918-सी 1973, जिसमें एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया गया था, अपील स्वयं खारिज होने के मद्देनजर खारिज कर दी गई है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा